

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या: 25/2024

दायर दिनांक: 19.06.2024

निर्णय दिनांक 22.12.2025

—: अनवान :-

श्रीमति सीमा कुंवर पिता श्री नरपत सिंह जी चुण्डावत (पति श्री महावीर सिंह राठोड) उम्र 38 वर्ष निवासी गुडा दुर्जन सिंह, गुडा राम सिंह, पाली (राज.) हाल निवासी भीमनगर डिंडोली सूरत गुजरात

— अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमति मीठू कुंवर पति श्री नरपत सिंह जी चुण्डावत उम्र वयस्क निवासी भेरुदास जी का खेड़ा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) हाल निवासी उदावतो का खेड़ा आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमति बेबी कुंवर पिता श्री मोहन सिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी मोरडीया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 08/10/2001 जो विद्ववान न्यायालय तहसीलदार सा० आमेट जिला राजसमन्द द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में फरमाया गया है।

उपस्थित :-

1. श्री सुनिल कुमार बोहरा, अधिवक्ता अपीलांत
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3

—: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 76 फैसल दिनांक 08.10.2001 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया/अपीलार्थीया के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति श्री नरपत सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी चुण्डावत निवासी



*Handwritten signature/initials*

भेरुदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) थे, जिनका स्वर्गवास 1992 में हो चुका है। श्री नरपत सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी चुण्डावत निवासी भेरुदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भेरुदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) में कृषि भूमिया स्थित है, जिनके खाता संख्या 44, 45, 46, 47 है। खाता संख्या 44 में 4 खसरे व रकबा 5.6100 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 45 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 46 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 47 में 20 खसरे व रकबा 7.7200 हेक्टर भूमि स्थित है। श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, प्रार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 को उनके हको से महरूम कर संपत्ति को हड़पने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 3 से मिलीभगत करके स्वर्गीय श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी पत्नी होना गलत वर्णित करके केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 के ही जीवित विधिक उत्तराधिकारी होना वर्णित कर जानबुझकर मिथ्या एवं झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य नामान्तरकरण आदेश प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में दिनांक 08.10.2001 को किया गया है। जिसमे न तो कोई जाँच की गई है और नही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवैध होने से खारिज होने योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर सत्यापन किए जाने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य व आधार उपलब्ध नहीं होते हुए प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में आंकड़ो कि पूर्ति करने हेतु सामान्य प्रक्रिया (Routine Process) अपनाते हुए अति संक्षिप्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध फरमाया गया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध, अनरिजन्ड है तथा स्पीकिंग आर्डर भी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूचि के अनुसार पुत्र, पुत्री, व पत्नी को ही विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। कानूनन द्वितिय पत्नी को न तो विधिक पत्नी माना गया है और नहीं विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। फिर भी विद्ववान अवर न्यायालय द्वारा बिना कोई जाँच किए, आंख बंद कर, बिना कोई मस्तिष्क उपयोग किए ही आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित किया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर अवैध है। विद्ववान अवर न्यायालय द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि के मामले में स्पष्ट त्रुटि की ही है, साथ ही एक अवैध, अनुचित, अनियमित एवं अनुपयुक्त आदेश फरमाया गया है, जिससे स्पष्ट न्याय का हनन होता है। जो कानूनन निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थिया/अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर विद्ववान अवर न्यायालय तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमन्द द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर प्रमाणित/सत्यापन प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में दिनांक 08.10.2001 को किया गया है, जिसके नामान्तरकरण संख्या 76 है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश को निरस्त फरमाया जाकर स्वर्गीय श्री नरपत सिंह के बजाय प्रार्थिया/अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण के आदेश फरमाया जाने की कृपा करावें।



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना दिनांक 03.10.2025 को अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांत ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया/अपीलार्थिया के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति श्री नरपत सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह जी चुण्डावत निवासी भेरुदास जी का खेडा पोस्ट गोवल पंचायत समिति सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.) थे, जिनका स्वर्गवास 1992 में हो चुका है। श्री नरपत सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भेरुदास जी का खेडा में कृषि भूमिया स्थित है, जिनके खाता संख्या 44, 45, 46, 47 है। खाता संख्या 44 में 4 खसरे व रकबा 5.6100 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 45 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 46 में 1 खसरा व रकबा 0.0300 हेक्टर भूमि, खाता संख्या 47 में 20 खसरे व रकबा 7.7200 हेक्टर भूमि स्थित है। श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, प्रार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 को उनके हक से महरूम कर संपत्ति को हड़पने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 3 से मिलीभगत करके स्वर्गीय श्री नरपत सिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनकी पत्नी होना गलत वर्णित करके केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 के ही जीवित विधिक उत्तराधिकारी होना वर्णित कर जानबुझकर मिथ्या एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य नामान्तरकरण आदेश प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2001 में दिनांक 08.10.2001 को किया गया है। जिसमें न तो कोई जाँच की गई है और नही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शून्य होकर, अवैध होने से खारिज होने योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर सत्यापन किए जाने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य व आधार उपलब्ध नहीं होते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2001 में आंकड़ों की पूर्ति करने हेतु सामान्य प्रक्रिया (Routine Process) अपनाते हुए अति संक्षिप्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध फरमाया गया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरुद्ध, अनरिजन्ड है तथा स्पीकिंग आर्डर भी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम सूचि के अनुसार पुत्र, पुत्री, व पत्नी को ही विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। कानूनन द्वितीय पत्नी को न तो विधिक पत्नी माना गया है और नहीं विधिक उत्तराधिकारी माना गया है। फिर भी विद्ववान अवर न्यायालय द्वारा बिना कोई जाँच किए, आंख बंद कर, बिना कोई मस्तिष्क उपयोग किए ही आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित किया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य होकर अवैध है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 08.10.2001 को अप्रास्त फरमाया जावे।



धर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अपीलांत मृतक काशतकार की पुत्री है जिसका नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 76 दिनांक 08.10.2001 में दर्ज नहीं किया गया है। इसमें मृतक की दो पत्नियाँ होना जाहिर हुआ है तथा नामांतरकरण मृतक की दूसरी पत्नि के नाम पर खोला जाना भी जाहिर हुआ है। इस संबंध में इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि काशतकार की मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरकरण खोला जाता है। लेकिन विचाराधीन प्रकरण में ऐसा नहीं होने से अपीलार्थीया का नाम दर्ज नहीं हुआ। जो कि होना चाहिए था। यह एक परिक्षण का विषय है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय पत्नि के क्या अधिकार होते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जानकारी किये बिना उक्त नामांतरकरण को फ़ैसल किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामांतरकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


### :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 76 दिनांक 08.10.2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार आमेट को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। कि मृतक काशतकार के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूचि के उत्तराधिकारियों की जाँच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से किया जाना सुनिश्चित करें।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद